



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1048]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 9, 2009/आषाढ़ 18, 1931

No. 1048]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 9, 2009/ASADHA 18, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2009

का.आ. 1676(अ).—जबकि भारत सरकार के एक आदेश द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी, 2005 के सं. का.आ. 147(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में केन्द्रीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो चुकी है;

और, जबकि केन्द्रीय सरकार का विचार है कि इस प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के नाम से (जिसे इसके बाद प्राधिकरण कहा जाएगा) एक प्राधिकरण का गठन करती हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :—

1. प्रधान सचिव, —अध्यक्ष
पर्यावरण, वन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,
आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
2. सचिव, राजस्व विभाग, —सदस्य
आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
3. निदेशक, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, —सदस्य
हैदराबाद

4. प्रो. डी. सत्यनारायणन, कोस्टल ऑशियन —सदस्य
मनीटोरिंग एंड प्रिडिक्शन सिस्टम, महासागर
विकास विभाग, प्लॉट सं. 51, पांडुरंगपुरम,
विशाखापट्टनम
5. प्रो. ए. वी. रमन, प्राणि, —सदस्य
विज्ञान और समुद्री जीव विज्ञान विभाग,
आंध्र प्रदेश, विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम
6. सदस्य सचिव, आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण —सदस्य
बोर्ड, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण
काम्प्लेक्स, हैदराबाद
7. डॉ. बी. आर. सुब्रमण्यम, सलाहकार, एकीकृत —सदस्य
तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन, महासागर
विकास विभाग, चैन्नई
8. डॉ. पार्तजलि शास्त्री, पर्यावरण केन्द्र, —सदस्य
म. सं. 86-4-16/1, मनथेना गार्डन्स,
राजामुंद्री-533003, पूर्वी गोदावरी जिला,
आंध्र प्रदेश
9. डॉ. डी. वी. भास्कर राव, प्रोफेसर ऑफ —सदस्य
मिटिऑरोलॉजी, मिटिऑरोलॉजी एंड
ऑशिफोनोग्राफी, विशाखापट्टनम-530003
10. निदेशक, रयोर एरिया डवलपमेंट प्राधिकरण, —सदस्य-
हैदराबाद सचिव

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा आंध्र प्रदेश राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों तथा तटीय जोन प्रबंध योजना (सी जैड एम पी) के वर्गीकरण में परिवर्तन या संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना और इस संबंध में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को सिफारिशें देना;

(ii) (क) उक्त अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, यहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनरावलोकन करना, और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देशित करना :

बशर्ते कि इस उप-पैरा के खण्ड (क) और (ख) के अंतर्गत आने वाले मामलों को अपनी ओर से अथवा किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधिक निकाय अथवा किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर शामिल किया गया है।

(iii) इस पैराग्राफ के उप-पैरा (i) और (ii) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन न होने के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें दर्ज करना;

(iv) इस पैराग्राफ के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना;

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय की दृष्टि के लिए अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके संशोधनों को, जांच और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, उन सभी विशिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा जोकि आंध्र प्रदेश की अनुमोदित तटीय प्रबंध योजना में निर्धारित की गई हैं।

IX. प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह माह में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X. प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि बैठकों के दौरान प्राधिकरण के दो-तिहाई सदस्य उपस्थित रहें।

XI. प्राधिकरण की पूर्वागामी शक्तियां और क्रियाकलाप केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन होंगे।

XII. प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित होगा।

XIII. ऐसा कोई मामला जो विशिष्टतया प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र और क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, उसे संबंधित साविधिक प्राधिकरण देखेगा।

[फा. सं. जे-17011/27/1999-आई ए-III]

डॉ. नलिनी पट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS ORDER

New Delhi, the 9th July, 2009

S.O. 1676(E).—Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 147(E), dated the 3rd February, 2005, the Central Government reconstituted the Andhra Pradesh Coastal Zone Management Authority, for period of three years and the term of the said Authority has been expired;

And whereas, the Central Government is of the view that such an Authority should be reconstituted;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Gujarat Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years with effect from the date of publication of this order, consisting of the following persons, namely :—

1. Principal Secretary, Environment, Forests and Sciences and Technology, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.

—Chairman

2. Secretary, Department of Revenue, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad. —Member
3. Director, National Remote Sensing Agency, Hyderabad. —Member
4. Prof. D. Satyanarayanan, Coastal Ocean Monitoring and Prediction System, Department of Ocean Development, Plot No. 51, Pandurangapuram, Visakhapatnam. —Member
5. Prof. A. V. Raman, Department of Zoology and Marine Biology, Andhra Pradesh University, Visakhapatnam. —Member
6. Member Secretary, Andhra Pradesh Pollution Control Board, Housing and Urban Development Authority Complex, Hyderabad. —Member
7. Dr. B.R. Subrahmaniam, Advisor, Integrated Coastal and Marine Area Management, Department of Ocean Development, Chennai. —Member
8. Dr. Patanjali Sastry, Environment Center, H. No 86-4-16/1, Manthana Gardens, Rajahmundry-533 003, East Godavari District, Andhra Pradesh. —Member
9. Dr. D.V. Bhaskar Rao, Professor of Meteorology, Department of Meteorology and Oceanography, Visakhapatnam-530 003. —Member
10. Director, Shore Area Development Authority Hyderabad. —Member-Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Andhra Pradesh, namely :—

- (i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Andhra Pradesh State Government and making specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority therefore;
- (ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable

to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under Section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority :

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II may be taken up *suo-motu* or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organization;

(iii) filing complaints, under Section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order;

(iv) to take action under Section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

- III. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government of Andhra Pradesh, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.
- IV. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.
- V. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas.
- VI. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.
- VII. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.
- VIII. The Authority shall ensure compliance of all

- specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Andhra Pradesh.
- IX. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.
- X. The Authority shall ensure that at least two third members of the Authority are present during the meetings.
- XI. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
- XII. The Authority shall have its headquarters at Hyderabad.
- XIII. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F.No. J-17011/27-1999-IA-III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'